बी डी एल सीएसआर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट

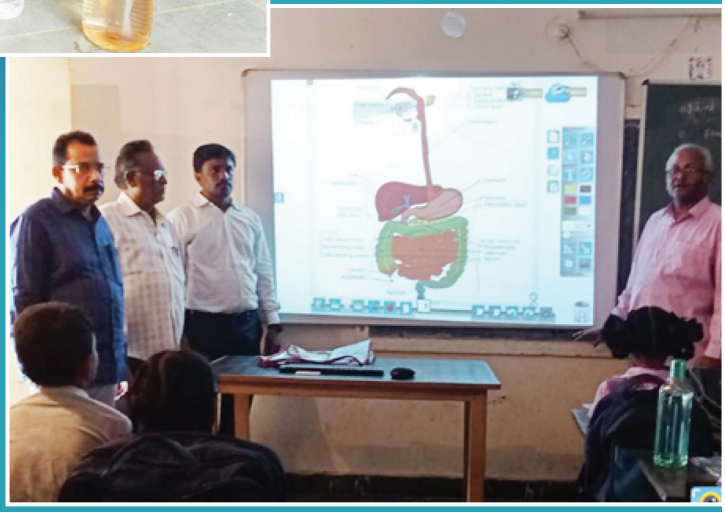

वित्तीय वर्ष 2022-23

Submitted to

भारत डायनामिक्स लिमिटेड
BHARAT DYNAMICS LIMITED

Submitted by

INSTITUTE OF PUBLIC ENTERPRISE
Shameerpet, Hyderabad

Acknowledgement

We are thankful to the executives of Bharat Dynamics Limited for their valuable inputs and coordination in conducting the Impact Assessment Study of 03 CSR projects of Bharat Dynamics Limited for FY 2022-23. On behalf of the IPE CSR Team, we extend our gratefulness to Commode A Madhavarao (Retd.), Chairman and Managing Director, BDL for providing us the opportunity to conduct the study.

A report of this nature requires an active association of professionals from the host organization. We express our heartfelt gratitude to Shri N Satyanarayana, Head-HR/CSR, Shri A. Sathesh Chakravarthi, DGM C-HR (TA&OD), and Smt A Nagalakshmi, DM C-HR (CSR) for providing us with the necessary support in gathering the data and completing the work on time.

Prof. S. Sreenivasa Murthy
Director,
Senior Professor and NLCIL Chair Professor on CSR

Dr. J. Kiranmai
Head – Centre for CG and CSR, IPE

विषय सूचिका

कार्यकारी सारांश 4

अध्याय I
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी: एक अवलोकन 6

अध्याय II
भारत डायनामिक्स लिमिटेड और इसकी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में 8

अध्याय III
अनुसंधान पद्धति और दृष्टिकोण 10

अध्याय IV
परियोजनावार प्रभाव विश्लेषण 11

परियोजना 1: अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से टीएस और एपी के सरकारी स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

परियोजना 2: विजयनगरम जिले के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम

परियोजना 3: शिक्षुओं को भुगतान की जाने वाली वृत्तिका (अर्थात शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत 2.5% न्यूनतम अधिदेश से अधिक)

कार्यकारी सारांश

बीडीएल समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर और जागरूक है। कंपनी ने अपनी सीएसआर नीति को कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के साथ संरेखित/संबद्ध (aligned) किया है और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों पर खर्च कर रही है। कंपनी; समुदाय, समाज और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को हल करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएगी, जिसमें विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं को रणनीतिक रूप से परियोजना मोड में लिया जाएगा। सीएसआर के तहत मुख्य ध्यान क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा, पोषण, शिक्षा और साक्षरता, कौशल विकास और स्वच्छता आदि पर हैं। बीडीएल ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आकांक्षी जिलों / अल्पविकसित क्षेत्रों में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों को शुरू किया है। बीडीएल अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी प्रयासों के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और समुदाय के भीतर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयास करती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर बजट ₹ 1319.32 लाख रुपए निर्धारित किया गया है।

आईपीई को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बीडीएल द्वारा शुरू की गई तीन सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया था, जिनमें से प्रत्येक का बजट एक करोड़ रुपये या उससे अधिक था। ये परियोजनाएं कम से कम एक वर्ष से संचालित हैं, जो बीडीएल को सेवा किए गए समुदायों की विकासात्मक आवश्यकताओं को संबोधित करने में उनकी सफलता का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करता है। आईपीई ने ओईसीडी डीएसी पद्धति का उपयोग किया, जो एक संपूर्ण मूल्यांकन पद्धति है, ताकि प्रत्येक परियोजना की प्रासंगिकता, सुसंगतता, दक्षता, प्रभावशीलता, प्रभाव और स्थिरता का विश्लेषण किया जा सके। इस दृष्टिकोण ने बेहतरीन कार्यान्वयन, संसाधनों के कुशल उपयोग और रणनीतिक उद्देश्यों के साथ जुड़ाव सुनिश्चित किया। आईपीई ने परिणामों को मापने पर विशेष जोर दिया, जिसमें लक्षित समुदायों द्वारा अनुभव किए गए सकारात्मक परिवर्तनों, जैसे सामाजिक-आर्थिक सुधार और बेहतर आजीविका अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

ढांचा/पद्धति: ओईसीडी डीएसी ढांचे/पद्धति का उपयोग बीडीएल की सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है। अध्ययन के तहत सभी परियोजनाओं के स्कोर इसकी प्रासंगिकता, दक्षता, प्रभावशीलता, प्रभाव और स्थिरता मापदंडों पर आधारित हैं।

परियोजना-वार प्रभाव नीचे दिया गया है

परियोजना 1: अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के सरकारी स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

भारत डायनामिक्स लिमिटेड, एक सामाजिक रूप से जागरूक रक्षा संगठन, भारत सरकार के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का समर्थन करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में कक्षा भूख की समस्या को संबोधित करना है। इन स्कूली बच्चों के अधिकांश लाभार्थी समाज के वंचित वर्गों से संबंधित हैं और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और विभिन्न राज्यों से आए प्रवासी परिवारों से हैं। अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ साझेदारी में, बीडीएल पिछले एक दशक से तेलंगाना राज्य के संगारेड्डी जिले के पटांचेरु मंडल और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर में सरकारी स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त पके हुए मध्याह्न भोजन को प्रायोजित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में,

बीडीएल ने अक्षय पात्र फाउंडेशन को ₹ 172.33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे उन्हें पटांचेरु के 63 चयनित स्कूलों में 6,483 स्कूली बच्चों और विशाखापत्तनम शहर के 12 चयनित स्कूलों में 3,831 स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन प्रायोजित करने में सक्षम बनाया गया।

परिणाम: बीडीएल ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से 10,314 छात्रों को भोजन प्रदान करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्कूली बच्चों के बीच कक्षा भूख को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया।

प्रभाव: बीडीएल द्वारा प्रायोजित मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों की ऊंचाई, वजन और समग्र स्वास्थ्य में सुधार किया है, जिसके परिणामस्वरूप एकाग्रता स्तर में वृद्धि और परियोजना स्कूलों में शिक्षा मानकों में वृद्धि हुई है।

परियोजना 2: विजयनगरम में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं

सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण और सीखने की सुविधाओं की कमी ने छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को बाधित किया है, जिसके कारण शिक्षा मानकों में गिरावट आई है। नतीजतन, सरकारी स्कूलों में स्कूली बच्चों की उपस्थिति और नामांकन भी प्रभावित हुआ है। इस समस्या को पहचानते हुए, आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण और सीखने की सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय लागू किए हैं। ऐसा ही एक उपाय कक्षाओं का डिजिटलीकरण है, जो भारत सरकार के 2018 में शुरू किए गए "समग्र शिक्षा परियोजना" के अनुरूप है। स्थानीय अधिकारियों के अनुरोधों का जवाब देते हुए, बीडीएल ने एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में, विजयनगरम जिले के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षा प्रणालियों की स्थापना के लिए सहयोग प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, बीडीएल ने ₹ 100 लाख रुपए की लागत से 40 स्मार्ट कक्षाएं सफलतापूर्वक स्थापित कीं। इसके बाद 2022-23 के दौरान ₹ 200 लाख की लागत से 72 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की गईं।

परिणाम: बीडीएल ने विजयनगरम जिले के चयनित सरकारी स्कूलों में 72 KYAN स्मार्ट कक्षा प्रणालियों को स्थापित करके परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त किया। इस कार्यक्रम से कुल 10,000 छात्रों को लाभ हुआ, जो विविध विषय सामग्री के साथ जुड़े और प्रतिदिन स्मार्ट कक्षा सत्रों में भाग लिया। नतीजतन, ऊपरी प्राथमिक और उच्च विद्यालयों ने प्रतिदिन 5-6 स्मार्ट कक्षा सत्र आयोजित किए, जिससे छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध हुए और गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैव विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी जैसे विभिन्न विषयों में उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में प्रगति हुई।

प्रभाव: विजयनगरम जिले, आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्थापित स्मार्ट कक्षा प्रणालियों ने कक्षा शिक्षण और सीखने के माहौल को बदल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा मानकों में सुधार, स्कूल नामांकन में वृद्धि, अनुपस्थिति में कमी और समग्र शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि हुई है।

परियोजना 3: प्रशिक्षुओं को वजीफा (अर्थात प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत 2.5% न्यूनतम अनिवार्यता से अधिक)

प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार, बीडीएल कई वर्षों से ट्रेड प्रशिक्षुता (पूर्व-आईटीआई) के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है ताकि कुल कार्यबल का 15% प्रशिक्षुओं के रूप में प्रशिक्षित हो सके। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 में, बीडीएल ने अपने प्रशिक्षुता कौशल विकास केंद्र की सुविधाओं और संसाधनों का उपयोग करके औसतन 550 स्नातक/आईटीआई/वैकल्पिक ट्रेड/तकनीकी/व्यावसायिक प्रशिक्षुओं को प्रति

माह प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध किया। इन 550 प्रशिक्षुओं के लिए औसतन प्रति माह होने वाले आवर्ती खर्च, जो बीडीएल के प्रशिक्षुता केंद्र में 9 विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित हुए, बीडीएल के सीएसआर द्वारा कवर किए गए, जिसमें वैधानिक मानदंडों से अधिक वजीफा शामिल था।

परिणाम: बीडीएल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान औसतन 550 आईटीआई/इंटरमीडिएट/स्नातक/एमबीए उम्मीदवार युवाओं को विभिन्न प्रशिक्षुता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करके अपने परियोजना उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। इन प्रशिक्षुओं ने उद्योग-विशिष्ट कौशल के साथ-साथ मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्राप्त किए। इसके अलावा, उन्हें एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि के लिए वजीफा प्रदान किया गया और विभिन्न उद्योगों में प्लेसमेंट या स्व-रोजगार के माध्यम से बेहतर आजीविका का अनुभव हुआ।

प्रभाव: इस परियोजना ने औसतन 550 आईटीआई/इंटरमीडिएट/स्नातक/एमबीए उम्मीदवार युवाओं पर प्रति माह महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिससे उनकी आत्मविश्वास में वृद्धि हुई ताकि वे संबंधित उद्योग में स्थापित हो सकें या उपयुक्त क्षेत्रों में नए उद्यमिता अवसरों में प्रवेश कर सकें। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक उम्मीदवार को पाठ्यक्रम के प्रकार के आधार पर 7000 से 16000 रुपए प्रति माह तक का वजीफा प्राप्त हुआ, जिससे उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुई। इसके अलावा, इस पहल ने विनिर्माण, निर्माण, बीपीओ और सेवा क्षेत्र उद्योगों को कुशल जनशक्ति प्रदान की।

अध्याय 1

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी: एक अवलोकन

कंपनियां न केवल अपनी लाभप्रदता और वृद्धि पर ध्यान देती हैं, बल्कि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) की अवधारणा के माध्यम से समाज और पर्यावरण की भलाई के लिए कल्याण और पर्यावरण गतिविधियों पर भी विचार करती हैं। सीएसआर को सामाजिक नीतियों, प्रथाओं और पहलों का एक व्यापक संग्रह माना जाता है जो व्यवसाय संचालन में एकीकृत होते हैं ताकि समाज की अपेक्षाओं और उनके व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) एक स्व-नियामक ढांचा है जो एक कंपनी को स्वयं, अपने हितधारकों और व्यापक समुदाय के प्रति जवाबदेही बनाए रखने में सक्षम बनाता है। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में शामिल

होकर, जिसे अक्सर कॉर्पोरेट नागरिकता कहा जाता है, संगठन अपने विभिन्न सामाजिक आयामों पर प्रभाव के प्रति सचेत हो सकते हैं, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारक शामिल हैं। सीएसआर में समाज में सार्थक योगदान देना और कर्मचारियों, ग्राहकों, शेयरधारकों, आपूर्तिकर्ताओं और आम जनता जैसे हितधारकों को पर्याप्त सेवाएं प्रदान करके संतुलित विकास को बढ़ावा देना शामिल है। मूल रूप से, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में वे रणनीतियाँ शामिल होती हैं जो कंपनियां अपने व्यवसाय संचालन को समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपनाती हैं, जिसमें स्थिरता, सामाजिक प्रभाव और संचालन में नैतिक प्रथाओं को संबोधित करना शामिल है।

समाज को वापस देना भारतीय संस्कृति और नैतिकता का एक मूलभूत घटक है, और पारंपरिक भारतीय उद्यमों ने शुरू से ही इस दृष्टिकोण को अपनाया है। हमारे पवित्र ग्रंथ समाज में योगदान देने के मूल्य पर जोर देते हैं। भारत की प्राचीन चेतना/सोच, जो आज भी मान्य है, व्यक्तियों को सभी हितधारकों की भलाई सुनिश्चित करने के अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। भारतीय उद्योग का सामाजिक रूप से जागरूक होने का इतिहास रहा है, और कुछ प्रमुख कंपनियों ने इस क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किए हैं।

कई वर्षों से विधायिका ने विभिन्न सामाजिक, श्रम और पर्यावरणीय कानून पारित किए हैं ताकि व्यवसायों को अपने कर्मचारियों, पड़ोसियों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने में मदद मिल सके। अधिनियम में सीएसआर उपायों को शामिल करना एक अभूतपूर्व विधायी पहल है ताकि निगमों को राष्ट्र के सामाजिक विकास प्रक्रिया में हितधारक के रूप में शामिल किया जा सके और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को मजबूत किया जा सके।

कंपनी अधिनियम 2013 एक ऐसा विधान है जिसने सीएसआर को अनिवार्य बनाने में दुनिया के सबसे बड़े प्रयोगों में से एक की शुरुआत की। सीएसआर सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी विचार है। सरकार सीएसआर को शामिल करके व्यवसायों को राष्ट्रीय विकास के एजेंडे में शामिल करने की कोशिश करती है। अधिनियम में सीएसआर प्रावधानों को शामिल करने के साथ, निगमों पर अब सामाजिक, पर्यावरणीय और वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कदम उठाने की कानूनी जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 135 और इसके द्वारा बनाए गए सीएसआर नियम भारत में सीएसआर के लिए कानूनी आधार के रूप में कार्य करते हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 ने 2014 में सीएसआर को अनिवार्य किया। तब से, भारत में सीएसआर के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए कई संशोधन और बदलाव पेश किए गए हैं। सीएसआर पहल का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से भारत को नया रूप देना है। हालांकि कई कॉर्पोरेट और औद्योगिक संगठनों द्वारा प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से ऐसा किया जाता रहा है, सीएसआर उन कंपनियों के लिए अनिवार्य हो गया है जो मानदंडों में आती हैं और कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में दी गई गतिविधियों को शुरू करें।

अध्याय II

भारत डायनामिक्स लिमिटेड और इसकी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में

भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बारे में

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) को 16 जुलाई, 1970 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इस उपक्रम के गठन का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के लिए ज़रूरी मिसाइल प्रणालियों और संबद्ध उपकरणों के विनिर्माण हेतु एक ठोस आधार तैयार करना था।

अपनी स्थापना के बाद से, बीडीएल डीआरडीओ और विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के साथ मिलकर भारतीय सशस्त्र बलों के लिए विभिन्न मिसाइलों और संबद्ध उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति के लिए काम कर रही है। राष्ट्र द्वारा स्वदेशी, परिष्कृत और समकालीन मिसाइलों को विकसित करने के लिए शुरू की गई एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) ने बीडीएल को इस कार्यक्रम में निकटता से शामिल होने का अवसर दिया, जिसमें इसे प्राथमिक उत्पादन एजेंसी के रूप में पहचाना गया। इससे उन्नत विनिर्माण और कार्यक्रम प्रबंधन प्रौद्योगिकियों और कौशलों को आत्मसात करने के लिए ढेर सारे अवसर खुले। आज, बीडीएल दुनिया के उन कुछ उद्योगों में से एक के रूप में विकसित हुई है जिनके पास भारतीय सशस्त्र बलों के लिए निर्देशित मिसाइलों, जल के नीचे हथियारों, हवाई उत्पादों और संबद्ध रक्षा उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। कंपनी उत्पाद जीवन चक्र समर्थन और पुरानी मिसाइलों के नवीनीकरण / जीवन विस्तार की भी पेशकश करती है।

बीडीएल में सीएसआर

भारत डायनामिक्स लिमिटेड समाज की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताओं को हल करने पर ध्यान देती है। बीडीएल की सीएसआर पहल राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित (aligned) हैं और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में कॉर्पोरेट क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाती हैं। कंपनी स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है, साथ ही स्थानीय क्षेत्रों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाए रखती है।

सीएसआर गतिविधियों के क्षेत्र

कंपनियों द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीतियों में शामिल की जा सकने वाली गतिविधियाँ निम्नलिखित हो सकती हैं:

- भूख, गरीबी और कुपोषण को खत्म करना, स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना जिसमें निवारक स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता शामिल है, जिसमें स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।

- शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल शामिल हैं, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और अलग-अलग सक्षम लोगों के बीच, और आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ।

- लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएँ स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय।

- पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पति और जीव-जंतुओं की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी के पुनर्जनन के लिए स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान शामिल है।

- राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति की सुरक्षा, जिसमें ऐतिहासिक महत्व के भवनों और स्थलों और कलाकृतियों का पुनरुद्धार शामिल है; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का संवर्धन और विकास।

- सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) के सेवानिवृत्त और उनके आश्रितों सहित विधवाओं के लाभ के उपाय।

- ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण।

- प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) या केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान।

- A. विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान।

- B. सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित विश्वविद्यालयों; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी); राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों में योगदान।

- ग्रामीण विकास परियोजनाएँ।

- झुग्गी क्षेत्र विकास।

- आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं।

बीडीएल ने अपनी सीएसआर गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए बोर्ड स्तर से नीचे सीएसआर और एसडी समिति, बोर्ड स्तर पर सीएसआर और एसडी समिति का गठन किया है।

अध्याय III

अनुसंधान पद्धति और दृष्टिकोण

प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का उद्देश्य परियोजनाओं के परिणामों और प्रभाव को निर्धारित करना है। आईपीई वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा किए गए 03 सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए ओईसीडी डीएसी नेटवर्क ऑन डेवलपमेंट इवैल्यूएशन ढांचे को अपनाता है और प्रत्येक सीएसआर परियोजना का बजट एक करोड़ से ऊपर था। प्रभाव के मानदंड चयनित परियोजना की प्रासंगिकता, दक्षता, प्रभावशीलता, प्रभाव, स्थिरता और सुसंगतता का अध्ययन करना है। ये मानदंड एक नियामक ढांचा प्रदान करते हैं जिसका उपयोग किसी हस्तक्षेप (नीति, रणनीति, कार्यक्रम आदि) की योग्यता या मूल्य निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

Source: OECD DAC Framework

अध्ययन संबंधित पद्धति का उपयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजेगा:

- सीएसआर परियोजना के इच्छित/योजनाबद्ध परिणाम क्या हैं?
- किन समूहों को परिवर्तनों से प्रभावित (या अप्रभावित) किया गया है?
- परियोजना को लागू करने की विधि क्या है और कार्यान्वयन एजेंसी को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यदि कोई हो?
- परियोजना हितधारकों की मांगों/अपेक्षाओं को पूरा करने में कितनी महत्वपूर्ण है?
- क्या परियोजना में स्थिरता है या नहीं?

अध्ययन का दायरा: अध्ययन का दायरा निम्नलिखित को शामिल करता है:

- मौजूदा परियोजना दस्तावेजों की समीक्षा जैसे परियोजना समझौता दस्तावेज, आधारभूत अध्ययन रिपोर्ट, यदि कोई हो, परियोजना प्रगति रिपोर्ट, पूर्णता रिपोर्ट।
- परियोजनाओं की सूची से नमूना चयन और हितधारक संतुष्टि स्तर सर्वेक्षण करना।

- प्रभाव से संबंधित परियोजना परिणामों का विश्लेषण और सारांश करना।
- अंतराल की पहचान करना और सिफारिशें तैयार करना।

विस्तृत अनुसंधान पद्धति

प्रभाव अध्ययन प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए चार-चरण संरचित को अपनाता है। कार्यक्रमों के प्रभावों का सटीक आकलन करने के लिए, अपनाई गई पद्धति यह सुनिश्चित करती है कि ओईसीडी डीएसी मूल्यांकन मानकों का पालन किया जाए।

अध्याय IV

परियोजनावार प्रभाव विश्लेषण

परियोजना 1: अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से टीएस और एपी के सरकारी स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

परियोजना का नाम	अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से टीएस और एपी के सरकारी स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम
परियोजना लागत	172.33 लाख
निष्पादन अवधि	2022-23
सीएसआर विषयगत क्षेत्र	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता सहित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना (अनुसूची VII, धारा 135, आइटम नंबर 1) शिक्षा को बढ़ावा देना (अनुसूची VII, धारा 135, आइटम नंबर 2)
एसडीजी लक्ष्य	
परियोजना का उद्देश्य	परियोजना का मुख्य उद्देश्य अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में सरकारी स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन खिलाने को प्रायोजित करना है।
कुल लाभार्थी	10314 स्कूली बच्चे

परियोजना की पृष्ठभूमि

प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीई) 15 अगस्त 1995 को बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाने के साथ-साथ नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति दर को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। वर्ष 2001 तक मध्याह्न भोजन योजना पके हुए मध्याह्न भोजन योजना में परिवर्तित हो गई जिससे यह सुनिश्चित

किया गया कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में प्रत्येक बच्चे को कम से कम 200 दिनों तक प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन युक्त पौष्टिक भोजन प्राप्त हो। यह पहल अनाज, दालों, सब्जियों और फलों से भरपूर भोजन प्रदान करती है, जो स्कूली बच्चों के बीच भूख और कुपोषण का प्रभावी ढंग से मुकाबला करती है। अनुसंधान इंगित करता है कि मध्याह्न भोजन के कार्यान्वयन से पोषण संबंधी स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, स्टंटिंग और वेस्टिंग में कमी आई है और स्कूल में उपस्थिति में वृद्धि हुई है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, एक सामाजिक रूप से जागरूक रक्षा संगठन, भारत सरकार के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का समर्थन करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से, वे पिछले एक दशक से तेलंगाना राज्य के संगारेड्डी जिले के पाटनचेरु मंडल और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम शहर में सरकारी स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त पके हुए मध्याह्न भोजन को प्रायोजित कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, बीडीएल ने अक्षय पात्र फाउंडेशन को रु. 172.33 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे उन्हें पटानचेरु के 63 चयनित स्कूलों के 6,483 स्कूली बच्चों और विशाखापट्टणम के 12 चयनित स्कूलों के 3,831 स्कूली बच्चों के लिए दोपहर का भोजन प्रायोजित करने में सक्षम बनाया गया।

परियोजना की पहल

क्रम संख्या	परियोजना स्थान	स्कूलों की कुल संख्या	मध्याह्न भोजन खिलाने के लिए दिनों की कुल संख्या बीडीएल द्वारा प्रायोजित की गई थी	कुल ताकत	कुल राशि
1	पटानचेरु	63	180 दिन (जुलाई 2022 से मार्च 2023)	6483	
2	विजाग	12	180 दिन (जुलाई 2022 से मार्च 2023)	3831	172.33 लाख
	कुल	75		10314	

अक्षय पात्र फाउंडेशन के बारे में

अक्षय पात्र फाउंडेशन (टीएपीएफ) एक स्वतंत्र धर्मार्थ ट्रस्ट है, जो देश में कक्षा की भूख और कुपोषण जैसे व्यापक सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए भारत सरकार की पीएम पोषण पहल (पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना) को लागू करने का प्रयास करता है। दि अक्षय पात्र फाण्उडेशन बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहन के रूप में हर स्कूल के दिन गर्म, पौष्टिक और स्वादिष्ट मध्याह्न भोजन प्रदान करने का प्रयास करता है। इस प्रकार, दृष्टि – 'भारत में कोई भी बच्चा भूख के कारण शिक्षा से वंचित नहीं होगा। वर्ष 2000 के बाद से, टीएपीएफ ने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की क्षमता का प्रभावी ढंग से उपयोग करके हर स्कूल के दिन पौष्टिक मध्याह्न भोजन के साथ बच्चों तक पहुंचने का प्रयास किया। रसोईघरों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करके और भारत सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, कॉर्पोरेट घरानों और परोपकारी लोगों के साथ साझेदारी करके, टीएपीएफ ने बड़े पैमाने पर एक सामाजिक कारण को संबोधित करने के लिए एक प्रणाली बनाई। वर्तमान में, टीएपीएफ भारत के 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 72 स्थानों पर 23,110 सरकारी स्कूलों और अंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे 2.2 मिलियन से अधिक बच्चों की सेवा करता है।

दोनों परियोजना स्थानों के लिए मेनू आइटम

क्रम संख्या	दिन	मेनू-पाटनचेरु	मेनू विशाखापत्तनम
1	सोमवार	वेजिटेबल पुलाव, मिक्स्ड वेजिटेबल करी ग्रेवी और स्नैक्स	गर्म पोंगल / वेजिटेबल पुलाव, ग्रेवी करी

क्रम संख्या	दिन	मेनू-पाटनचेरु	मेनू विशाखापत्तनम
2	मंगलवार	चावल, मिक्स वेजिटेबल सांभर, मिक्स्ड वेजिटेबल करी या वेजिटेबल करी और स्नैक्स	पुलिहोरा, डोंडाकाया, चटनी
3	बुधवार	चावल, पत्ता पप्पू (दाल), सब्जी करी और स्नैक्स	वेजिटेबल राइस, आलू कुर्मा
4	गुरूवार	वेजिटेबल बिरयानी, मिक्स्ड वेजिटेबल चना मसाला करी और स्नैक्स	सांभर बाथ / लेमन राइस, टमाटर की चटनी
5	शुक्रवार	चावल, मिक्स वेजिटेबल सांभर, मीठे चावल और स्नैक्स	चावल, पत्ता दाल करी
6	शानिवार	चावल, पत्ता पप्पू (दाल), सब्जी करी और स्नैक्स	हरी पत्ती चावल, पप्पू चारु, मीठा पोंगल

प्रभाव विश्लेषण ढांचा: आईपीई टीम ने सीएसआर परियोजना के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न मापदंडों के ओईसीडी डीएसी फ्रेमवर्क को नियोजित किया, और निष्कर्ष नीचे उल्लिखित हैं।

प्रासंगिकता: बीडीएल का यह प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के 75 स्कूलों के कुल 10,314 स्कूली बच्चों को पका हुआ मुफ्त मध्याह्न भोजन प्रदान करता है। इनमें से अधिकांश स्कूली बच्चे समुदायों के वंचित वर्गों से संबंधित हैं और विभिन्न राज्यों से आने वाले प्रवासी परिवारों से आते हैं। यह परियोजना प्रासंगिक है क्योंकि यह भारत सरकार की पीएम पोषण पहल के साथ संरेखित है, जिसे पहले मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता था। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में कक्षा की भूख के मुद्दे को संबोधित करना है, जो बदले में स्कूल छोड़ने वालों में कमी और स्कूल उपस्थिति और प्रतिधारण दर में वृद्धि में योगदान देता है।

दक्षता: अक्षय पात्र फाउंडेशन बीडीएल से वित्तीय मदद के साथ सरकारी स्कूलों में मुफ्त पके हुए मध्याह्न भोजन का त्वरित और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करता है। अक्षय पात्र फाउंडेशन गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्राप्त करता है, मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए सही तकनीक का उपयोग करता है, और भोजन वितरित करने के लिए सही वाहनों का उपयोग करता है।

प्रभावशीलता: बीडीएल ने अक्षयपात्र फाउंडेशन के माध्यम से 10,314 छात्रों को खिलाकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्कूली बच्चों के बीच कक्षा की भूख का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को 450 किलो कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान किया जाता है, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को 700 किलो कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। इसके अलावा, भोजन में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन ए जैसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, जो छात्रों के कल्याण और संज्ञानात्मक विकास में योगदान करते हैं।

प्रभाव: 10314 स्कूली बच्चों में से 80% गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से हैं, इनमें से 40% छात्र प्रवासी परिवारों से आते हैं। इन स्कूली बच्चों के अधिकांश माता-पिता मजदूरी मजदूर हैं, अक्सर सुबह जल्दी निकलते हैं और शाम को लौटते हैं, यह सुनिश्चित किए बिना कि उनके बच्चों को पर्याप्त रूप से खिलाया जाता है। पहले, कई छात्र खाली पेट कक्षाओं में आते थे, जिसके परिणामस्वरूप उपस्थिति दर में कमी आती थी और ड्रॉप आउट दर में वृद्धि होती थी। हालांकि, जब से बीडीएल ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन प्रदान करना शुरू किया है, आईपीई टीम ने स्कूल नामांकन में 1 फीसदी से 32 फीसदी तक उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। उदाहरण के लिए, जेडपीएचएस-मुथंगी, जिसमें पहले 187 छात्र थे, अब 247-2023 तक 24 छात्र हैं। विशाखापट्टणम के स्कूलों

में भी छात्रों की संख्या में मामूली सुधार हुआ है। इस पहल का पिछले वर्षों की तुलना में एक्स-क्लास सार्वजनिक परीक्षाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कुल मिलाकर, इस पहल से छात्रों की ऊंचाई, वजन और समग्र स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना स्कूलों में एकाग्रता के स्तर में वृद्धि हुई है और शैक्षिक मानकों में वृद्धि हुई है।

बीडीएल परियोजना के बाद स्कूल की ताकत पर प्रभाव

तेलंगाना राज्य

क्रम संख्या	स्कूल का नाम	2022-23 में संख्या	2023-24 में संख्या	वृद्धि प्रतिशत
1	एमपीपीएस-इसनापुर (I से V)	380	408	7%
2	एमपीपीएस-मुथांगी (I से V)	180	232	29%
3	एमपीपीएस-भानूर	73	79	8%
4	जेडपीएचएस भानूर	145	145	कोई बदलाव नहीं
5	जेडपीएचएस इस्नापुर	800	1000	25%
6	जेडपीएचएस मुथांगी	187	247	32%

आंध्र प्रदेश राज्य

क्रम संख्या	स्कूल का नाम	2022-23 में संख्या	2023-24 में संख्या	वृद्धि प्रतिशत
1	जीवीएमसी - गांधीग्राम	320	324	1%
2	जीवीएमसी कमला नेहरू हाई स्कूल - रेलवे न्यू कॉलोनी	386	387	-
3	जीवीएमसी हाई स्कूल - रेलवे न्यू कॉलोनी	329	333	1%

सम्बद्धता: यह परियोजना भारत सरकार की प्रसिद्ध मध्याह्न भोजन पहल पीएम पोषण के साथ संरेखित है और संबंधित राज्य सरकारों के मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों के साथ तालमेल बिठाती है।

परिणाम: इस परियोजना को लागू करने से, तेलंगाना राज्य के 63 सरकारी स्कूलों और आंध्र प्रदेश के 12 स्कूलों में मध्याह्न भोजन के मानक में काफी सुधार आया था। नतीजतन, कुल 10,314 स्कूली बच्चों को पोषित किया गया, जिससे उनके स्वास्थ्य, कल्याण और शैक्षिक परिणामों में उल्लेखनीय प्रगति हुई।

स्थिरता: इस परियोजना के परिणाम स्थायी हैं क्योंकि बीडीएल लगातार वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि अक्षय पात्र फाउंडेशन सक्रिय रूप से विभिन्न कॉर्पोरेट संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग की मांग करता है। इसके अलावा, एजेंसी इस परियोजना को विस्तारित अवधि के लिए बनाए रखने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और संसाधनों से लैस है।

परियोजना का प्रदर्शन

ओईसीडी डीएसी फ्रेमवर्क वेटेज स्कोर

मध्याह्न भोजन – पटानचेरु, तेलंगाना राज्य		
डीएसी फ्रेमवर्क पैरामीटर्स	**प्रदर्शन संकेतक**	**वेटेज स्कोर**
प्रासंगिकता	औसत से ऊपर	18
दक्षता	औसत से ऊपर	18
प्रभावशीलता	औसत से ऊपर	18
प्रभाव	औसत से ऊपर	18
स्थिरता	औसत से ऊपर	18
कुल स्कोर	**औसत से ऊपर**	**90**

मध्याह्न भोजन – विशाखापट्टणम		
डीएसी फ्रेमवर्क पैरामीटर्स	**प्रदर्शन संकेतक**	**वेटेज स्कोर**
प्रासंगिकता	अति उत्कृष्ट	19
दक्षता	अति उत्कृष्ट	18
प्रभावशीलता	अति उत्कृष्ट	18
प्रभाव	अति उत्कृष्ट	17
स्थिरता	अति उत्कृष्ट	18
कुल स्कोर	**अति उत्कृष्ट**	**90**

व्यक्तिगत स्कोर: अति उत्कृष्ट: 17-20; औसत से ऊपर: 13-16; औसत 9-12; औसत से कम: 5 to 8 और बहुत ख़राब: 1 to 4

कुल स्कोर: अति उत्कृष्ट (Scores: 81 to 100); औसत से ऊपर (61 to 80); औसत (41 to 60); औसत से कम (21 to 40) और बहुत ख़राब (1 to 20)

संतुष्टि स्तर सर्वेक्षण

I. पटानचेरु

अ) छात्रों की संतुष्टि स्तर सर्वेक्षण

प्राथमिक स्कूली बच्चों का सर्वेक्षण

हाल ही में, आईपीई टीम ने एमपीपीएस-इसनापुर, एमपीपीएस-मुथंगी और एमपीपीएस भानपुर के 90 प्राथमिक स्कूली बच्चों को एक प्रश्नावली दी, जिसमें प्रत्येक स्कूल में 30 छात्रों का नमूना आकार था और नमूने IV और V कक्षा के स्कूली बच्चों से लिए गए थे।

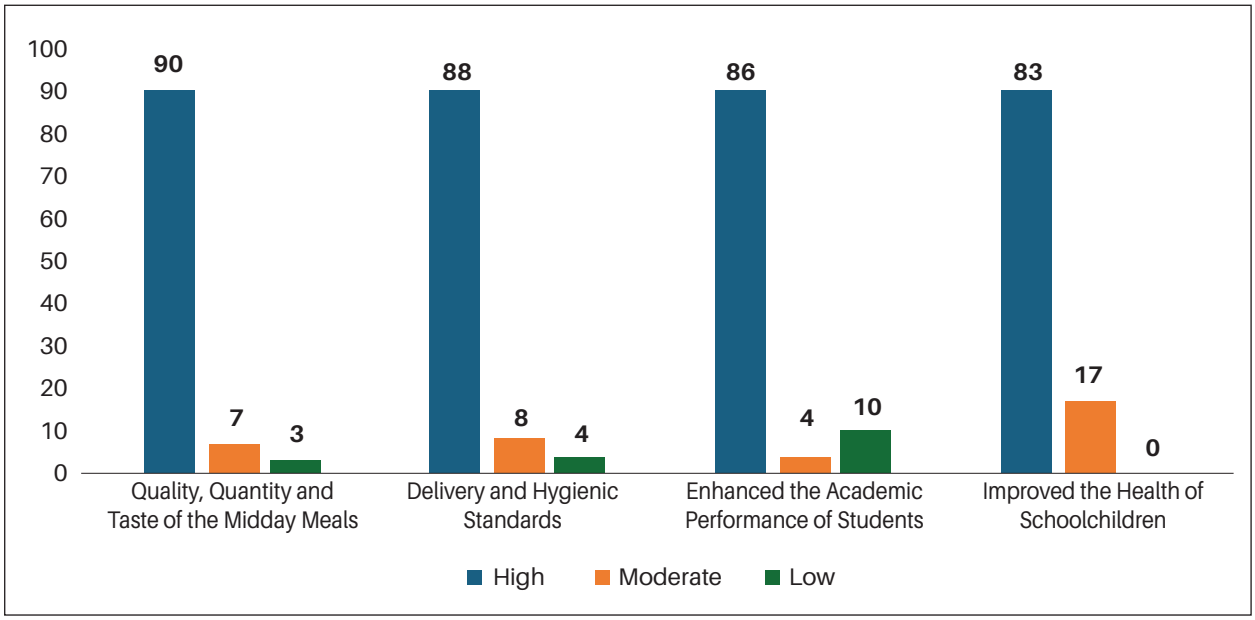

90% छात्रों ने इस परियोजना द्वारा प्रदान किए गए मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और स्वाद के साथ अपनी उच्च संतुष्टि व्यक्त की। इसके अलावा, 88% छात्रों ने परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा बनाए गए वितरण और स्वच्छ मानकों के साथ अपनी उच्च संतुष्टि प्रकट की। इसके अतिरिक्त, 86% उत्तरदाता बीडीएल की मध्याह्न भोजन परियोजना का उपभोग करने के बाद छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में वृद्धि से अत्यधिक संतुष्ट थे और अंत में 83% छात्रों ने इस परियोजना के कारण स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार के साथ अपनी उच्च संतुष्टि साझा की।

जिला परिषद हाई स्कूल के बच्चों का सर्वेक्षण

आईपीई टीम ने जेडपीएचएस मुथंगी, जेडपीएचएस भानूर और जेडपीएचएस इसनापुर के 60 स्कूली बच्चों के साथ काम किया। उन्होंने प्रत्येक स्कूल को एक प्रश्नावली दी, जिसमें प्रत्येक के लिए 20 का नमूना आकार था। छात्रों ने बड़े पैमाने पर दोपहर के भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और स्वाद के साथ-साथ उनके वितरण की समय की पाबंदी और स्वच्छता मानकों के साथ उच्च संतुष्टि की सूचना दी। इसके अलावा, उन्होंने अपने संबंधित स्कूलों में इन मध्याह्न भोजन का सेवन करने के परिणामस्वरूप उनके स्वास्थ्य और शैक्षिक विकास पर लाभकारी प्रभावों के साथ संतोष व्यक्त किया।

ब) अभिभावक संतुष्टि स्तर सर्वेक्षण: आईपीई टीम ने तेलंगाना राज्य के पटानचेरु मंडल में तीन प्राथमिक विद्यालयों और संबंधित तीन जिला परिषद हाई स्कूलों के कुल 60 माता-पिता के साथ काम किया। सभी अभिभावकों ने सरकारी स्कूलों में प्रदान किए जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया। इसके अलावा, उन्होंने स्कूलों में भोजन वितरण के लिए लागू कुशल कार्यक्रम की सराहना की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अपने बच्चों की शैक्षणिक और स्वास्थ्य स्थितियों में देखे गए संवर्द्धन के साथ बहुत संतोष व्यक्त किया।

स) शिक्षक संतुष्टि स्तर सर्वेक्षण: आईपीई टीम ने सक्रिय रूप से विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों के तीन प्रधानाध्यापकों के साथ-साथ तीन जिला परिषद उच्च विद्यालयों से एक ही नंबर तीन प्रधानाध्यापहरियों के साथ काम किया। इसके अतिरिक्त, टीम ने प्राथमिक विद्यालयों के 15 एसजीटी शिक्षकों और जिला परिषद हाई स्कूलों के 15 स्कूल सहायकों के साथ साक्षात्कार आयोजित किए। प्राथमिक और जिला परिषद उच्च विद्यालयों दोनों की अधिकांश प्रधानाध्यापिकाओं और शिक्षकों ने कार्यान्वयन एजेंसी अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा खाद्यान्न की खरीद और मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए रसोई शेडों में उन्नत तकनीकों के उपयोग के साथ अपनी उच्च स्तर की संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने स्कूलों में भोजन के समय पर वितरण की भी सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप स्कूल अनुपस्थिति में कमी, स्कूल नामांकन में वृद्धि और इस परियोजना में शामिल छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ।

II. विशाखापट्टनम

अ) छात्र संतुष्टि स्तर सर्वेक्षण: आईपीई टीम ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से बीडीएल द्वारा प्रदान किए गए मध्याह्न भोजन पर प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए जीवीएमसी हाई स्कूल - गांधीग्राम, जीवीएमसी कमला नेहरू गर्ल्स हाई स्कूल - रेलवे न्यू कॉलोनी और जीवीएमसी हाई स्कूल: जीवीएमसी हाई स्कूल के 30 छात्रों के साथ काम किया। टीम ने अपने नमूना चयन में ग्रेड आठवीं, नौवीं और दसवीं से लड़कों और लड़कियों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। बीडीएल फंड के समर्थन से अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा पेश किए गए 'मिड डे मील' की गुणवत्ता, मात्रा और स्वाद के साथ महत्वपूर्ण 93% छात्रों ने अपनी अत्यंत संतुष्टि व्यक्त की। इसके अलावा, 91% प्रतिभागियों ने अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा बनाए गए वितरण और स्वच्छता मानकों के साथ अपनी उच्च संतुष्टि व्यक्त की। इसके अलावा, 88% उत्तरदाताओं ने बीडीएल-प्रायोजित मध्याह्न भोजन का सेवन करने के बाद अपने शैक्षणिक प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार की सूचना दी। अंत में, 92% छात्रों ने इस पहल द्वारा प्रदान किए गए पौष्टिक

भोजन का उपभोग करने के बाद ऊंचाई और वजन के मामले में स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव के साथ अपनी संतुष्टि साझा की।

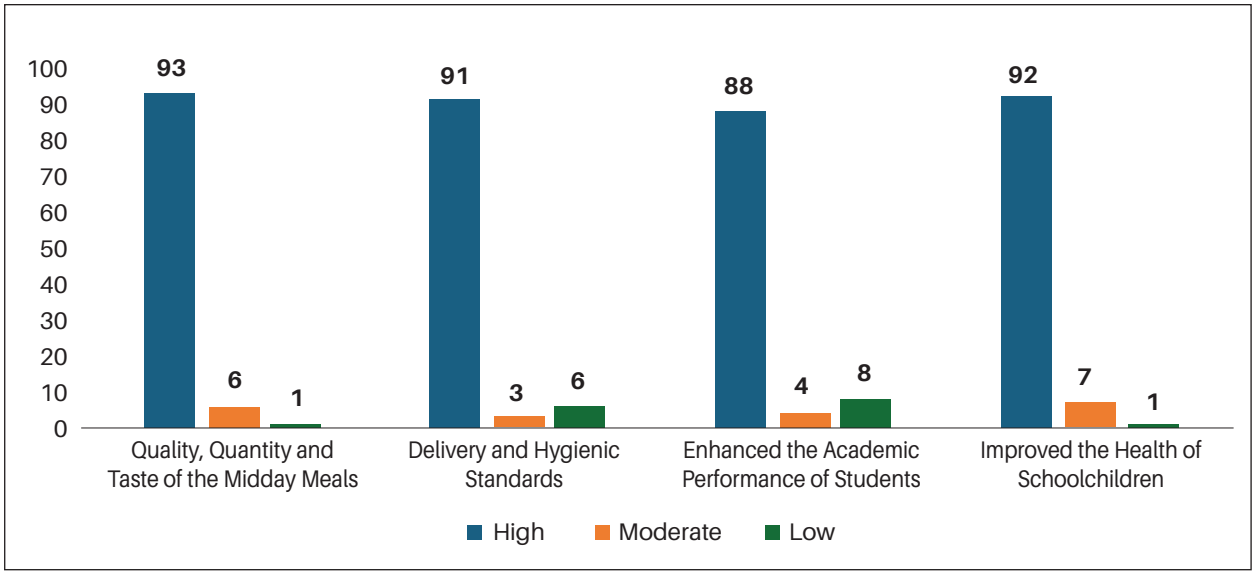

ब) अभिभावक संतुष्टि स्तर सर्वेक्षण: आईपीई टीम ने तीन स्कूलों के 30 माता-पिता के साथ काम किया, जिनमें से सभी ने मेनू आइटम के साथ-साथ दोपहर के भोजन के दौरान अपने बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और मात्रा के साथ अपनी उच्च संतुष्टि व्यक्त की। इसके अतिरिक्त, ये माता-पिता इन संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली मध्याह्न भोजन और शिक्षा दोनों की असाधारण गुणवत्ता के कारण अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेज रहे हैं। इसके अलावा, वे इन स्कूलों में मध्याह्न भोजन का सेवन करने के बाद अपने बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन और उनके स्वास्थ्य के स्तर में उल्लेखनीय सुधार के साथ अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

स) शिक्षक संतुष्टि स्तर सर्वेक्षण: आईपीई टीम ने तीन स्कूलों के 15 शिक्षकों के साथ बातचीत की, जिनमें से सभी ने इस पहल के माध्यम से सरकारी स्कूलों में पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता वाले मध्याह्न भोजन की आपूर्ति करने में अक्षय पात्र और बीडीएल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि इन मिड-डे मील में अनाज और बाजरा, दालें, तेल और वसा के साथ-साथ पत्तेदार और गैर-पत्तेदार सब्जियों का एक संतुलित संयोजन होता है, जो छात्रों की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और बच्चों के समग्र विकास में योगदान करने की क्षमता को बढ़ाता है। सभी शिक्षकों ने अपने छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए बीडीएल और अक्षय पात्र फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया।

समग्र अवलोकन

- अध्ययन स्पष्ट रूप से हितधारकों की संतुष्टि, बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि, उपस्थिति में वृद्धि और नामांकन वृद्धि पर परियोजना के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।
- कई स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के कारण दोपहर की उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें नाश्ता भी शामिल है।
- अक्षयपात्र फाउंडेशन अच्छी तरह से तैयार, पेशेवर है, और समय पर बच्चों को भोजन तैयार करने, पहुँचाने और वितरित करने के लिए सभी पोषण और सुरक्षा मानकों का पालन करता है।
- अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने स्कूलों के दैनिक संचालन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। पहले, हेडमास्टर/हेडमिस्ट्रेस, शिक्षक और अन्य कर्मचारी मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की खरीद और पके हुए भोजन की तैयारी

और सेवा सुनिश्चित करने पर केंद्रित थे। इसके अलावा, शिक्षकों पर दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आधार पर मिड-डे मील कार्यक्रम के लिए बिल तैयार करने की जिम्मेदारी थी। इस स्थिति का स्कूल के सुचारू संचालन पर हानिकारक प्रभाव पड़ा और शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता हुआ। हालांकि, इस परियोजना के कारण, शिक्षकों के पास अब कक्षा शिक्षण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों को समर्पित करने के लिए पर्याप्त समय है।

- स्कूलों ने पुष्टि की है कि मिड-डे मील वैन लगातार सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के निर्धारित समय सीमा के भीतर स्कूल पहुंचती है। इसके बाद दोपहर 12.30 बजे से 1.30 बजे के बीच बच्चों को भोजन परोसा जाता है। अक्षय पात्र के फील्ड अधिकारी नियमित रूप से स्कूलों का दौरा करते हैं और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता के बारे में स्कूल शिक्षकों, बच्चों और अभिभावकों सहित विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रिया एकत्र करते हैं। वे इन हितधारकों द्वारा प्रदान किए गए सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार करते हैं और परियोजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करते हैं।

केस स्टडीज

केस स्टडी 1

"मेरा नाम अमरीश है, और मैं वर्तमान में एमपीपीएस - इसनापुर में पांचवीं कक्षा में पढ़ रहा हूं। हमारा परिवार पांच साल पहले बिहार के देवरिया जिले के एक सुदूर गांव से इस्नापुर चला आया था। मेरा छोटा भाई, आयुष भी उसी स्कूल में चौथी कक्षा का छात्र है। मेरे पिता एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि मेरी माँ दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती है। मेरे माता-पिता दोनों सुबह जल्दी घर से निकल जाते हैं और शाम को लौट आते हैं। दुर्भाग्य से, हमारे परिवार की परिस्थितियों के कारण, वे हमें पर्याप्त भोजन प्रदान करने के लिए संघर्ष करते हैं। हालांकि, बीडीएल की सहायता से, अक्षयपात्र फाउंडेशन ने दोपहर में पौष्टिक भोजन प्रदान किया, जिससे मेरी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की मेरी क्षमता में काफी सुधार हुआ है और मेरे समग्र स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है"।

अमरीश,
कक्षा 5 का छात्र, एमपीपीएस - इस्नापुर

बीडीएल ने एक बयान में कहा, "बीडीएल के उदार प्रायोजन ने यह सुनिश्चित किया कि अक्षय पात्र द्वारा प्रदान किया जाने वाला मिड-डे मील न केवल पौष्टिक था, बल्कि अनुशंसित आहार मानकों के अनुरूप भी था। पूरे सप्ताह के व्यापक मेनू में चावल, सब्जी बिरयानी, सब्जी पुलाव, मिश्रित सब्जी करी, मिश्रित सब्जी सांभर, पत्ता पप्पू (दाल), सब्जी करी, मीठे चावल और स्नैक्स जैसे व्यंजनों की एक विविध श्रेणी पेश की गई। इन भोजनों को आवश्यक प्रोटीन और पोषक तत्वों से पैक किया गया था, जिससे बच्चों के बीच एकाग्रता के स्तर में सुधार, स्वास्थ्य में वृद्धि और शैक्षणिक उपलब्धियां हुईं। यह सकारात्मक प्रभाव स्कूल के नामांकन में स्पष्ट था, जो 180 से बढ़कर 232 हो गया, जिससे प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को लाभ हुआ"।

श्रीमती बी ललिता,
प्रधानाध्यापिका, एमपीपीएस – मुथांगी

तेलंगाना राज्य में मिड-डे-मील स्कूल

आंध्र प्रदेश में मिड डे मील स्कूल

परियोजना 2: विजयनगरम जिले के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम

परियोजना का नाम	विजयनगरम जिले के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम
परियोजना लागत	200 लाख
निष्पादन अवधि	2022-23
सीएसआर विषयगत क्षेत्र	शिक्षा को बढ़ावा देना (अनुसूची VII, धारा 135, आइटम नंबर 2)
एसडीजी लक्ष्य	
परियोजना का उद्देश्य	परियोजना का उद्देश्य विजयनगरम जिले के चयनित सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षा प्रणाली प्रदान करके सरकारी स्कूलों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है।
कुल लाभार्थी	10000 स्कूली बच्चे

परियोजना की पृष्ठभूमि

सरकारी स्कूलों में अपर्याप्त आधुनिक शिक्षण और सीखने की सुविधाओं ने छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न की है, जिससे शिक्षा मानकों में गिरावट आई है। नतीजतन, स्कूली बच्चों की उपस्थिति और सरकारी स्कूलों में नामांकन भी प्रभावित हुआ है। इस मुद्दे को स्वीकार करते हुए, आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में अध्ययन और अध्यापन सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है। ऐसी ही एक पहल कक्षाओं का डिजिटलीकरण है, जो 2018 में शुरू की गई भारत सरकार की "समग्र शिक्षा परियोजना" के साथ संरेखित है। स्थानीय अधिकारियों के अनुरोध पर एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई बी डी एल ने विजयनगरम जिले के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, बीडीएल ने 100 लाख रुपये की लागत से 40 स्मार्ट क्लासरूम सफलतापूर्वक स्थापित किए। इसके बाद 2022-23 के दौरान 200 लाख रुपये की लागत से 72 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए।

परियोजना की पहल

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बीडीएल ने विजयनगरम जिले के चयनित सरकारी स्कूलों में 72 केवाईएन स्मार्ट क्लासरूम सफलतापूर्वक स्थापित किए, जिसमें आरईएस टेक्नोलॉजी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। परियोजना की कुल लागत 200 लाख रुपये थी, जिससे कुल 10000 छात्र लाभान्वित हुए। स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड ने इस पहल में तकनीकी भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की मंडलवार कुल संख्या

निष्पादन अवधि: सितंबर 2022 से मार्च 2023

क्रम संख्या	मंडल का नाम	स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम इंस्टालेशन के लिए मंडलवार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	जिला परिषद हाई स्कूल / सरकारी हाई स्कूल	एपीएसडब्ल्यूआरएस/ केजीबीवी स्कूल	कुल
1	बोब्बिली	02	02	-	-	04
2	रामभद्रपुरम	05	-	-	-	05

क्रम संख्या	मंडल का नाम	स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम इंस्टालेशन के लिए मंडलवार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	जिला परिषद हाई स्कूल / सरकारी हाई स्कूल	एपीएसडब्ल्यूआरएस/ केजीबीवी स्कूल	कुल
3	भोगापुरम	01	-	-	-	01
4	बदंगी	02	01	-	-	03
5	थर्लम	02	01	-	-	03
6	दातिराजेरु	02	02	-	-	04
7	गजपतिनगरम	01	-	-	-	01
8	बोंडापल्ली	02	01	-	-	03
9	गुरला	03	-	-	-	03
10	नेल्लीमारला	02	-	-	-	02
11	गण्त्यादा	05	-	-	-	05
12	जामी	01	-	-	-	01
13	राजम	04	04	05	-	13
14	आर.अमदलवलसा	01	02	05	01	09
15	वंगारा	-	-	05	02	07
16	संथाकविति	-	04	03	01	08
	कुल	33	17	18	04	72

के-यान स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम के बारे में

के-यान स्मार्ट क्लासरूम - विभिन्न घटक

के-यान (ज्ञान यंत्र) – एकीकृत प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षण समाधान: के-यान स्कूलों के भीतर एक इंटरैक्टिव सीखने के माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक समाधान के रूप में कार्य करता है। यह लागत प्रभावी तरीके से छात्र और शिक्षकों की जरूरतों को पूरा करता है, पाठ्यक्रम के साथ संरेखित प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया सामग्री के एकीकरण के माध्यम से उन्नत सीखने, समझ और प्रदर्शन के अवसर प्रदान करता है। समाधान को शिक्षकों को सशक्त बनाने पर ध्यान देने के साथ विकसित किया गया है, जिससे उन्हें कक्षा में एक मनोरम सीखने का अनुभव बनाने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, एकीकृत सामुदायिक कंप्यूटर अंतर्निहित अन्तरक्रियाशीलता के

साथ आता है, किसी भी सतह को एक इंटरैक्टिव कक्षा में बदल देता है, सीमित बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों में लाभ प्रदान करता है।

विस्तृत जानकारी

- कंप्यूटर (सीपीयू: इंटेल कोर i5 प्रोसेसर, चिपसेट: इंटेल, मेमोरी: 8 जीबी रैम, ग्राफिक्स: एकीकृत ग्राफिक्स, भंडारण: न्यूनतम 1 टीबी, ऑपरेटिंग सिस्टम: विंडोज 10 एसई)
- प्रोजेक्टर (चमक: 3500 एक्सजीए एएनएसआई लुमेन (शॉर्ट थ्रो), 800X600 रिज़ॉल्यूशन, कंट्रास्ट अनुपात: 18000: 1 या उच्चतर, लैंप लाइफ: 15000 घंटे (मानक मोड), 10000 घंटे (ब्राइट मोड))
- इन-बिल्ट इंटरएक्टिविटी (इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो किसी भी दीवार (सफेद रंग) के उपयोग को एक इंटरैक्टिव कक्षा (स्पर्श आधारित) के रूप में समर्थन करती है।)
- डिजिटल पेन (लिखने के लिए आईआर-आधारित डिजिटल पेन)
- कीबोर्ड और माउस (वायरलेस)
- बिल्ट ऑडियो सिस्टम में (ऑडियो: वॉल्यूम कंट्रोल के साथ 30W ऑडियो स्पीकर)
- यूएसबी पोर्ट (6 नंबर यूएसबी पोर्ट)
- बाहरी डिवाइस कनेक्टिविटी पोर्ट (वीजीए / एचडीएमआई पोर्ट)
- कनेक्टिविटी (ईथरनेट: इंटरनेट और वाईफाई के लिए लैन कनेक्टिविटी: 802.11 बी / जी / एन)
- इनबिल्ट कैमरा (बैक और फ्रंट कैमरा - (वैकल्पिक))

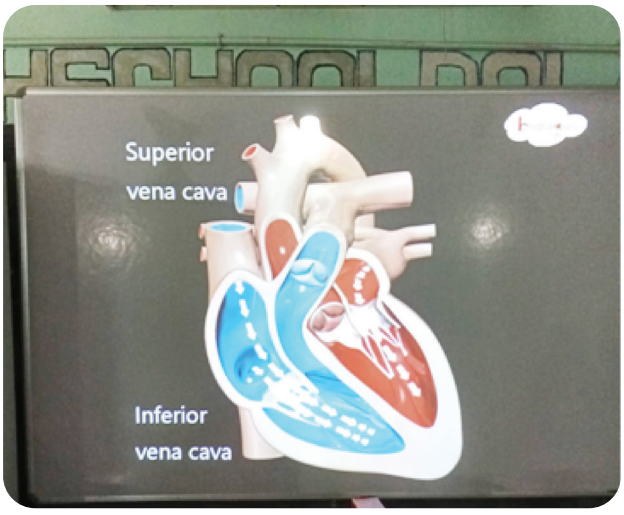

एमपीयूपीएस-अंतकापल्ली और जीएचएस में स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम - राजम

प्रभाव विश्लेषण ढांचा: आईपीई टीम ने सीएसआर परियोजना के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न मापदंडों के ओईसीडी डीएसी फ्रेमवर्क को नियोजित किया, और निष्कर्ष नीचे उल्लिखित हैं।

प्रासंगिकता: यह परियोजना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विजयनगरम जिले के चुने हुए सरकारी स्कूलों में परिवर्तनकारी बदलाव लाती है। यह कक्षा निर्देश और सीखने में डिजिटल परिवर्तन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की पहल के साथ-साथ भारत सरकार की सम्मानित समग्र शिक्षा परियोजना को भी मजबूत समर्थन प्रदान करता है, जो शिक्षा प्रणाली

की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण और सीखने के संसाधनों की आवश्यकता पर जोर देता है।

दक्षता: इस पहल को चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाते हुए, विनिर्दिष्ट समय-सीमा का पालन करते हुए और निधियों के उचित आबंटन के साथ व्यवस्थित तरीके से निष्पादित किया गया है। इसके अलावा, शिक्षक और छात्र के-यान स्मार्ट कक्षा प्रणालियों का इष्टतम उपयोग करते हैं। शिक्षक विभिन्न विषयों के छात्रों की समझ को बढ़ाने के लिए कक्षा सत्रों के दौरान प्रीलोडेड विषय सामग्री, ई-पुस्तकें, वीडियो व्याख्यान, इंटरैक्टिव लर्निंग टूल और यूट्यूब से डाउनलोड किए गए पाठ जैसी विभिन्न प्रकार की डिजिटल सामग्री का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, छात्रों के पास डिजिटल संसाधनों और ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, छात्र पारंपरिक पाठ्यपुस्तकों से परे जानकारी का पता लगा सकते हैं, विभिन्न विषयों की अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। नतीजतन, छात्र विषय वस्तु को अधिक आसानी से समझ सकते हैं और अपने शैक्षणिक मूल्यांकन में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।

प्रभावशीलता: बीडीएल ने विजयनगरम जिले के चयनित सरकारी स्कूलों में 72 केवाईएन स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम स्थापित करके परियोजना के उद्देश्य को हासिल किया। इस कार्यक्रम से कुल 10,000 छात्र लाभान्वित हुए, जो विविध विषय सामग्रियों से जुड़ते हैं और प्रतिदिन स्मार्ट कक्षा सत्रों में भाग लेते हैं। नतीजतन, उच्च प्राथमिक और उच्च विद्यालयों ने प्रति दिन 5-6 स्मार्ट कक्षा सत्र आयोजित किए, छात्रों के सीखने के अनुभवों को समृद्ध किया और गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव-विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी जैसे विभिन्न विषयों में उनके अकादमिक प्रदर्शन में प्रगति में योगदान दिया।

परिणाम

- सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण सुविधाओं में सुधार
- विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करने में छात्रों के तर्क, विश्लेषणात्मक और तार्किक कौशल को बढ़ाया।
- तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में छात्रों के एल एस आर डब्ल्यू (LSRW) कौशल में सुधार।
- विज्ञान विषय में छात्रों के ड्राइंग और व्यावहारिक कौशल को बढ़ाया।
- महाद्वीपों, महासागरों, देशों और भारतीय राज्यों को विभिन्न प्रकार के भौगोलिक मानचित्रों पर पहचानने की छात्रों की क्षमता को बढ़ाया गया था।

प्रभाव: अधिकांश छात्र कृषि, श्रम-गहन कार्य, जाति से संबंधित व्यवसायों, छोटे व्यवसायों या निजी क्षेत्र में लगे परिवारों से हैं। अतीत में, उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को भौतिक विज्ञान, जैविक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन और विभिन्न भाषाओं जैसे विषयों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तरफ़ा संचार के साथ पारंपरिक कक्षा शिक्षण अक्सर छात्र ऊब और विभिन्न लाइव अनुभव ऑडियो-वीडियो दृश्यों के बिना कक्षा की भागीदारी में रुचि की कमी का कारण बनता है। हालांकि, इस परियोजना ने परंपरागत रूप में कक्षाओं में होने वाले अध्ययन और अध्यापन के वातावरण को बदल दिया है, जिससे शैक्षिक मानकों में सुधार हुआ है, स्कूल नामांकन में वृद्धि हुई है, अनुपस्थिति कम हुई है और सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है।

सम्बद्धता: यह परियोजना तेलंगाना सरकार और भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित स्कूली शिक्षा पर विभिन्न नीतियों के अनुसार है।

स्थिरता: परियोजना के परिणामों का स्थायी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्राप्तकर्ता स्कूलों को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी से तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही शिक्षा विभाग, स्कूल विकास और प्रबंधन समिति और संबंधित स्थानीय निकाय से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें से सभी निरंतर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं परियोजना की सफलता।

परियोजना का प्रदर्शन

ओईसीडी डीएसी फ्रेमवर्क वेटेज स्कोर

डीएसी फ्रेमवर्क पैरामीटर्स	प्रदर्शन संकेतक	वेटेज स्कोर
प्रासंगिकता	अति उत्कृष्ट	18
दक्षता	अति उत्कृष्ट	18
प्रभावशीलता	अति उत्कृष्ट	18
प्रभाव	अति उत्कृष्ट	18
स्थिरता	अति उत्कृष्ट	17
कुल स्कोर	अति उत्कृष्ट	89

व्यक्तिगत स्कोर: अति उत्कृष्ट: 17-20; औसत से ऊपर: 13-16; औसत 9-12; औसत से कम: 5 to 8 और बहुत ख़राब: 1 to 4

कुल स्कोर: अति उत्कृष्ट (Scores: 81 to 100); औसत से ऊपर (61 to 80); औसत (41 to 60); औसत से कम (21 to 40) और बहुत ख़राब (1 to 20)

संतुष्टि स्तर सर्वेक्षण

लाभार्थी सर्वेक्षण विवरण

क्रम संख्या	आईपीई टीम ने स्कूल के नाम का दौरा किया	कुल संख्या	प्रश्नावली भरने के लिए चयन कक्षाएं	प्रश्नावली की कुल संख्या
1	एमपीयूपीएस - अंथाकापल्ली (पहली से आठवीं)	125 (लडके: 55 और लडकिया: 70)	सातवीं और आठवीं	30 (लडके: 15 और लडकिया: 15)
2	गवर्नमेंट हाई स्कूल - राजम	826 (लडके: 466 और लडकिया: 360)	आठवीं, नौवीं और दसवीं	30 (लडके: 15 और लडकिया: 15)
3	जेडपीएचएस - पोगिरी	508 (लडके: 236 और लडकिया: 272)	आठवीं, नौवीं और दसवीं	30 (लडके: 15 और लडकिया: 15)
4	जेडपीएचएस - कंचाराम	444 (लडके: 225 और लडकिया: 219)	आठवीं, नौवीं और दसवीं	30 (लडके: 15 और लडकिया: 15)
5	गवर्नमेंट हाई स्कूल - डोलापेट	664 (लडके: 337 और लडकिया: 327)	आठवीं, नौवीं और दसवीं	30 (लडके: 15 और लडकिया: 15)
6	एमपीपी स्कूल, पुलिस स्टेशन रोड, राजम	292 (लडके: 143 और लडकिया: 149)	-	-

अ) छात्र: आईपीई टीम ने विजयनगरम जिले के पांच जिला परिषद हाई स्कूलों से सातवीं से दसवीं कक्षा के 150 छात्रों के बीच संतुष्टि स्तर का सर्वेक्षण किया। प्रत्येक स्कूल में 30 प्रश्नावली का नमूना आकार था। 150 छात्रों में से 75 लड़के और 75 लड़कियां थीं। परिणामों से पता चला कि 81% छात्रों ने अपने स्कूलों में नियमित स्मार्ट कक्षा शिक्षण के साथ उच्च संतुष्टि व्यक्त की। अधिकांश छात्रों ने उल्लेख किया कि गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषाओं सहित विभिन्न कक्षाओं के लिए उनके स्कूल में औसतन 5-6 स्मार्ट कक्षा सत्र आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, 79% उत्तरदाताओं ने प्रीलोडेड विषय सामग्री, ई-लाइब्रेरी सामग्री, डाउनलोड किए गए पाठ और वीडियो की उपलब्धता के साथ उच्च संतुष्टि का खुलासा किया। दसवीं कक्षा के छात्र मुख्य रूप से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए इन सामग्रियों का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, छात्रों ने संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अपने नियमित पाठ्यक्रम में किए गए परिवर्तनों के अनुसार विषयों की सामग्री को अपडेट करने का अनुरोध किया। विशेष रूप से, 91% छात्रों ने KYAN स्मार्ट कक्षा प्रणाली के साथ बेहतर कक्षा शिक्षण और सीखने से अत्यधिक संतुष्ट होने की सूचना दी। उन्होंने पारंपरिक शिक्षण विधियों और KYAN स्मार्ट कक्षा प्रणाली के बीच अंतर पर प्रकाश डाला, छात्रों की रुचि और समझ को बढ़ाने में लाइव प्रदर्शनों के महत्व पर जोर दिया। अंत में, 86% उत्तरदाताओं ने अपने स्कूलों में स्मार्ट कक्षा सत्रों में भाग लेने के बाद अपने समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार के साथ उच्च संतुष्टि व्यक्त की।

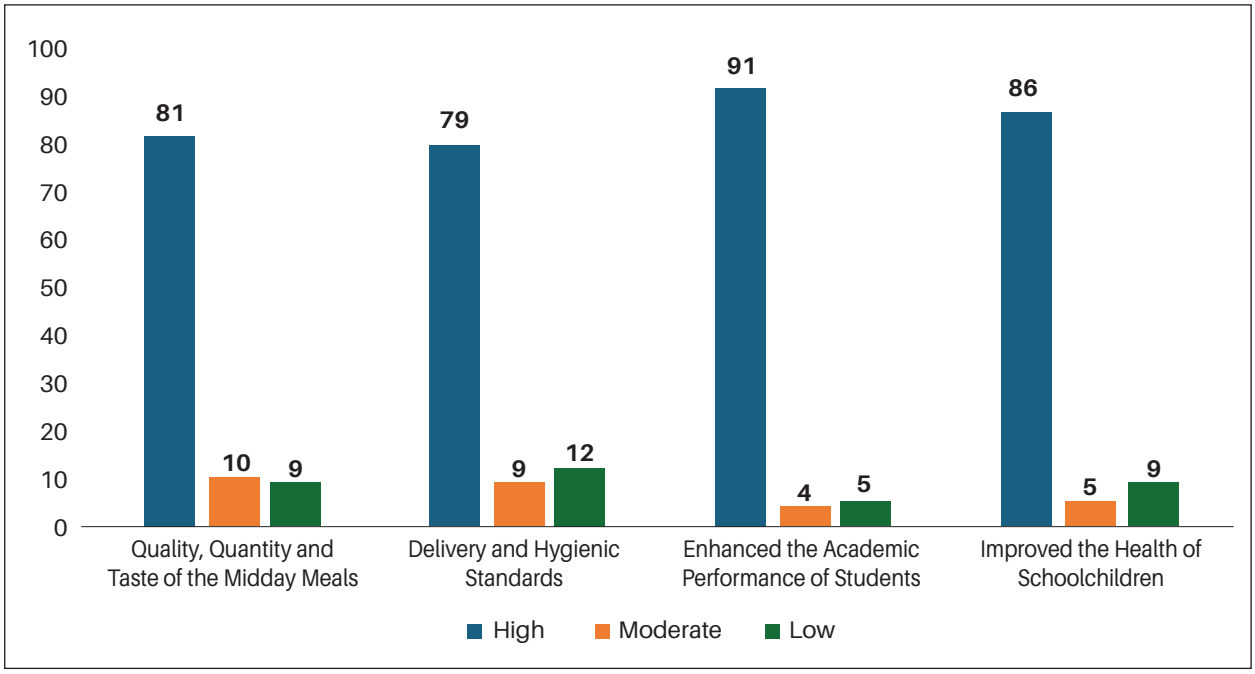

ब) शिक्षक: आईपीई टीम ने छह सरकारी स्कूलों के 24 शिक्षकों के साथ बातचीत की, जिनमें से सभी ने केवाईएएन स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम द्वारा प्रदान की गई उन्नत कक्षा शिक्षण और सीखने की सुविधाओं के साथ अपनी संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने छात्रों को रसायन विज्ञान के व्यावहारिक पाठ देने में इन प्रणालियों के महत्व पर जोर दिया, विशेष रूप से वे जो सुरक्षा जोखिमों के कारण पारंपरिक रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं में आयोजित नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा, शिक्षकों ने खराब प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए निदानात्मक कक्षाएं आयोजित करने में स्मार्ट कक्षा प्रणालियों के महत्व पर प्रकाश डाला, जो सीखने के लिए अधिक इंटरैक्टिव और दोहराव वाला दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों ने स्मार्ट प्रोजेक्टर का उपयोग करके अपने आधुनिक शिक्षण कौशल को बढ़ाने के अवसर के लिए सराहना व्यक्त की, जिससे वे छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन प्रदान कर सकें और अधिक प्रभावी पाठ योजनाएं विकसित कर सकें। इस परियोजना ने न केवल छात्र प्रगति का आकलन करने की उनकी क्षमता में सुधार किया है बल्कि उन्हें अधिक आकर्षक पाठ बनाने के लिए भी प्रेरित किया है।

स) अभिभावक: आईपीई टीम ने छह स्कूलों के चौबीस अभिभावकों के साथ बातचीत की, जिनमें से सभी ने बीडीएल द्वारा स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के बाद सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण सुविधाओं के साथ अपनी उच्च संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने अपने स्कूलों को ये स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध कराने के लिए बीडीएल को धन्यवाद ज्ञापित किया और कक्षा निर्देश तथा सीखने के माहौल में सुधार को स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा का मानक प्राप्त हुआ।

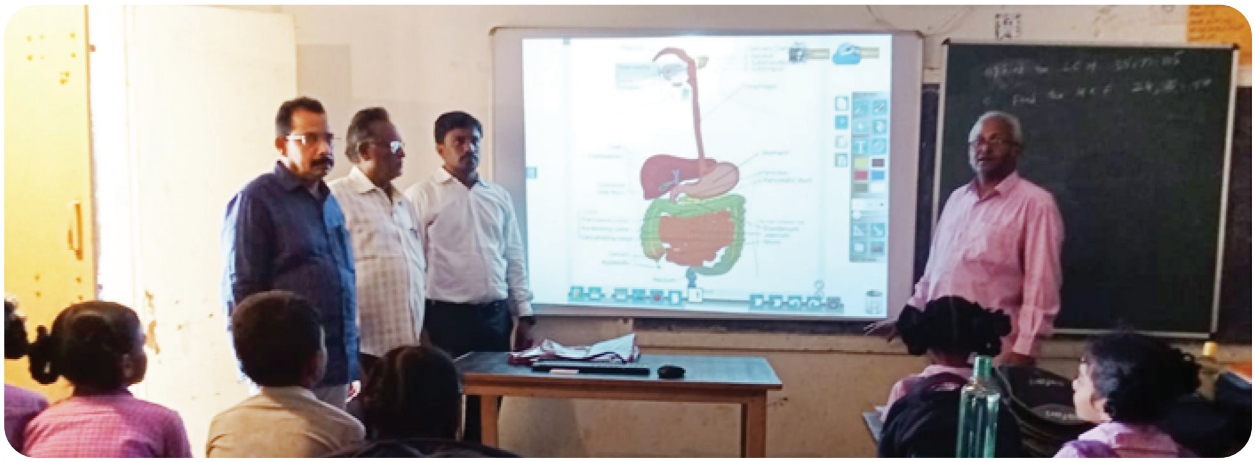

पोगिरी के जिला परिषद हाई स्कूल में स्मार्ट कक्षा सत्र

समग्र अवलोकन

- सभी शैक्षणिक संस्थानों ने स्मार्ट कक्षाओं की सफल स्थापना और वारंटी अवधि के दौरान सामने आए स्मार्ट कक्षा प्रणालियों के मुद्दों के समय पर समाधान की सूचना दी है। हालांकि, वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद स्कूलों के एक छोटे प्रतिशत को हार्डवेयर या सिस्टम समस्याओं का सामना करना पड़ा।
- डिजिटल लर्निंग पहल ने शिक्षकों और छात्रों दोनों से महत्वपूर्ण भागीदारी प्राप्त की है। गणित और विज्ञान ने उपयोग दरों को 70% से अधिक दिखाया है, जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है।
- शिक्षक डाउनलोड किए गए यू-ट्यूब वीडियो के माध्यम से विज्ञान प्रयोगों - भौतिकी, रसायन विज्ञान और जैविक विज्ञान का प्रदर्शन करके स्कूली बच्चों को व्यावहारिक लाइव अनुभव प्रदान करते हैं।
- शिक्षक अंग्रेजी व्याकरण के साथ छात्रों के अभ्यास के लिए अंग्रेजी वर्कशीट तैयार करते हैं।
- शिक्षक सामाजिक अध्ययन अवधारणाओं को समझाने के लिए डाउनलोड किए गए भौगोलिक मानचित्रों, स्थानों, दृश्यों, वीडियो का उपयोग करते हैं।
- शिक्षक तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं के लिए छात्रों के सुनने और कहानी कहने के कौशल में सुधार के लिए डाउनलोड किए गए वीडियो का उपयोग करते हैं।
- स्कूल में आमतौर पर साप्ताहिक रूप से 25-30 स्मार्ट कक्षा सत्र आयोजित किये जाते हैं।
- डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के लाभों में नई अवधारणाओं की सरलीकृत व्याख्या, छात्र जुड़ाव में वृद्धि, आधुनिक शिक्षण विधियों और कम प्रशिक्षकों के साथ कुशल प्रबंधन शामिल हैं।
- विभिन्न विषयों के लिए प्रीलोडेड सामग्री आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ संरेखित होती है।
- अधिकांश स्कूल छात्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उपचारात्मक कक्षाओं के लिए स्मार्ट कक्षाओं का उपयोग करते हैं।

केस स्टडीज

केस स्टडी 1

"हमारे स्कूल को के-यान स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम के प्रावधान के माध्यम से कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के प्रति भारत डायनामिक्स लिमिटेड की प्रतिबद्धता से समृद्ध किया गया है। वीडियो और 3D एनिमेशन के रूप में प्रीलोडेड विषय सामग्री के साथ पूर्ण यह प्रणाली कई लाभ प्रदान करती है। स्टाइलस पेन सुविधा शिक्षण सत्रों के दौरान वास्तविक समय एनोटेशन की अनुमति देती है, जिसके परिणामस्वरूप समय की बचत होती है। वीडियो व्याख्यान अवधारणाओं की तेजी से समझ में सहायता करते हैं, जबकि गतिविधियों और प्रयोगों के 3 डी एनिमेशन पारंपरिक पाठ्यपुस्तक विधियों से परे समझ को बढ़ाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म छात्रों को गहराई से पाठों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे सभी छात्रों के लिए बोर्ड की स्पष्ट दृश्यता सुनिश्चित होती है। शिक्षक की अनुपस्थिति में, अन्य शिक्षक विषय को कवर करने के लिए निर्बाध रूप से कदम उठा सकते हैं। अंत में, छात्रों को बेहतर भाषा कौशल का अनुभव होता है क्योंकि उन्हें जटिल शब्दों को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आसान लगता है, जिससे भविष्य के लिए उनके संचार कौशल में वृद्धि होती है"।

श्रीमती एन शर्मिला रानी,
वरिष्ठ सहायक, जैविक विज्ञान शिक्षक, जीएचएस - राजम

केस स्टडी 2

"मैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड को हमें के-यान स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम प्रदान करने के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना जहां छात्र कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अपरिचित हैं, इस प्रणाली ने छात्रों को विभिन्न अवधारणाओं के साथ जुड़ने और गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषाओं जैसे विषयों से लाभ उठाने की अनुमति दी है। स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम ने छात्रों के बीच सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया है, विशेष रूप से 7वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित जैसे मुख्य विषयों में। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों ने अवधारणाओं को प्रस्तुत करने और धीमी गति से सीखने वालों के साथ अपनी गति से चर्चा करने के लिए इसे फायदेमंद पाया है। उपकरण ने विभिन्न परियोजनाओं की छात्र प्रस्तुतियों की सुविधा भी प्रदान की है, विशेष रूप से जीव विज्ञान में, जैसे पौधों, पंखों और खाद्यान्नों का संग्रह"।

श्री पी श्रीनिवास राव,
हेडमास्टर, एमपीयूपीएस – अंतकापल्ली

केस स्टडी 3

"के-यान स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम में पहले से लोड किए गए विषयों की सामग्री की विविध रेंज स्कूली बच्चों के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होती है, उनकी रुचि को बढ़ाती है और उनका ध्यान आकर्षित करती है। स्केचमेट्री सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, छात्र ज्यामिति आकृतियों और कोणों के निर्माण को सहजता से समझ सकते हैं, जबकि केवाईएन द्वारा प्रदान किया गया स्टाइलस पेन भौतिक विज्ञान और जीव-विज्ञान के लिए आरेखों के ड्राइंग की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, छात्र इस अभिनव स्मार्ट कक्षा प्रणाली का उपयोग करके दस्तावेजों और वीडियो जैसे प्रासंगिक अध्ययन सामग्री तक आसानी से पहुंच सकते हैं"।

के हिमला,
IX कक्षा – ईएम, जेडपीएचएस- कांचारम, राजम मंडल, विजयनगरम जिला

परियोजना 3: शिक्षुओं को भुगतान की जाने वाली वृत्तिका (अर्थात शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत 2.5% न्यूनतम अधिदेश से अधिक)

विभिन्न प्रमुख लाभार्थियों के विवरण और अध्ययन विधि उपकरण:

परियोजना का नाम	शिक्षुओं को भुगतान किया जाने वाला वजीफा (अर्थात अपरेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत 2.5% न्यूनतम अधिदेश से अधिक)
परियोजना लागत	300 लाख
निष्पादन अवधि	2022-23
सीएसआर विषयगत क्षेत्र	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित शिक्षा को बढ़ावा देना (अनुसूची VII, धारा 135, आइटम नंबर 2)
एसडीजी लक्ष्य	
परियोजना का उद्देश्य	बीडीएल सीएसआर फंडिंग के तहत विभिन्न ट्रेडों में व्यापार शिक्षुता (एक्स-आईटीआई) के लिए बीडीएल के शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षुओं के लिए वृत्तिका भुगतान कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।
कुल लाभार्थी	500 प्रशिक्षु

परियोजना की पृष्ठभूमि

किसी भी देश की औद्योगिक उन्नति के लिए मानव संसाधन की प्रगति आवश्यक है। कौशल वृद्धि मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अकेले शैक्षणिक संस्थानों में प्रदान किया गया प्रशिक्षण कौशल अधिग्रहण के लिए अपर्याप्त है और कार्यस्थल प्रशिक्षण द्वारा पूरक होना चाहिए। शिक्षु अधिनियम, 1961 की स्थापना उद्योग की कुशल जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योग सुविधाओं का पूरी तरह से उपयोग करने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ की गई थी। प्रारंभ में, अधिनियम ने व्यापार शिक्षुओं के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण को कवर किया और बाद में क्रमशः स्नातक, तकनीशियन, तकनीशियन (व्यावसायिक), और वैकल्पिक व्यापार शिक्षुओं को शामिल करने के लिए 1973, 1986 और 2014 में संशोधन किया गया। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) वर्ष में दो बार (अक्तूबर/नवम्बर और अप्रैल/मई) व्यवसाय शिक्षुओं के लिए अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा (एआईटीटी) आयोजित करती है। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी) उन लोगों को प्रदान किए जाते हैं जो एआईटीटी पास करते हैं। एनएसी को सरकारी/अर्ध-सरकारी विभागों/संगठनों में रोजगार के लिए मान्यता प्राप्त है।

शिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार, बीडीएल कई वर्षों से शिक्षुओं के रूप में कुल कार्यबल के 2.5% को प्रशिक्षित करने के लिए व्यापार शिक्षुता (पूर्व-आईटीआई) के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 में, बीडीएल अतिरिक्त 500 स्नातक/आईटीआई/वैकल्पिक ट्रेड/तकनीकी/व्यावसायिक

शिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए अपने शिक्षुता कौशल विकास केंद्र की सुविधाओं और संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीडीएल के शिक्षुता केन्द्र में 9 विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित इन अतिरिक्त 500 शिक्षुओं के आवर्ती व्यय बीडीएल के सीएसआर द्वारा कवर किए गए थे, जिसमें सांविधिक मानदंडों से अधिक वजीफे भी शामिल थे।

परियोजना की पहल

शिक्षु अधिनियम-1961 और इससे संबंधित नियमों और विनियमों के अनुसार, 30 या उससे अधिक कार्यबल वाले उद्योगों को न्यूनतम 2.5% और अधिकतम 15% प्रशिक्षुओं को नियुक्त करना होगा। 2.5% न्यूनतम जनादेश से अधिक और ऊपर शिक्षुता से जुड़ी किसी भी लागत को सीएसआर फंडिंग के माध्यम से वित्तपोषित किया जा सकता है। बीडीएल वर्तमान में सरकारी निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न 9 ट्रेडों में व्यापार शिक्षुता के लिए अपने शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षुओं के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। बीडीएल ने शिक्षु अधिनियम, 1961 द्वारा अनिवार्य 2.5% न्यूनतम आवश्यकता को पार करते हुए, प्रति माह 500 प्रशिक्षुओं के वजीफे को कवर करने के लिए अपने सीएसआर के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 300 लाख रुपये निर्धारित किए हैं।

(i) बीडीएल शिक्षु प्रशिक्षण:

- चयनित 9 ट्रेडों जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मेकेनिक, मशिनिस्ट, मशिनिस्ट ग्राइंडर, मेकेनिक डिसेल, मैकेनिक आर एंड एसी, टर्नर, वेल्डर) में ट्रेड अपरेंटिस – आईटीआई पाठ्यक्रम।
- ग्रेजुएट और डिप्लोमा अपरेंटिस (सीएसई, ईसीई, ईईई, मैकेनिकल, सिविल और अन्य)
- इंटरमीडिएट वोकेशनल अपरेंटिस (ऑफिस असिस्टेंट, अकाउंट्स एंड टैक्सेशन और कंप्यूटर साइंस),
- वैकल्पिक ट्रेड / एमआईटी अपरेंटिस: (एमबीए (एचआर) और एमबीए (बिजनेस डेवलपमेंट)

(ii) 2022-23 के लिए कुल उम्मीदवार और बजट: वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रति माह औसतन 500 शिक्षुओं की कुल संख्या और आवंटित बजट प्रति वर्ष तीन करोड़ है

शिक्षु का प्रकार	बीडीएल द्वारा प्रति माह भुगतान की जाने वाली वृत्तिका	प्रति एक उम्मीदवार एक वर्ष के लिए व्यय	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रति माह शिक्षुओं की कुल संख्या को प्रशिक्षित किया गया	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 500 शिक्षुओं की वृत्तिका और उनके प्रशिक्षण खर्च पर कुल व्यय
स्नातक	9000	108000	500 प्रशिक्षु	
आईटीआई	8050	96600		300 लाख
वैकल्पिक व्यापार	16000	192000		
तकनीकी	8000	96000		
व्यवसायिक	7000	84000		

प्रभाव विश्लेषण ढांचा: आईपीई टीम ने सीएसआर परियोजना के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न मापदंडों के ओईसीडी डीएसी फ्रेमवर्क को नियोजित किया, और निष्कर्ष नीचे उल्लिखित हैं।

प्रासंगिकता: बीडीएल सीएसआर फंडिंग के तहत, विभिन्न आईटीआई/तकनीकी और अन्य पाठ्यक्रमों के शिक्षुओं के लिए 2.5% अधिदेश को पार करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न ट्रेडों और पाठ्यक्रमों में कौशल विकास प्रशिक्षण और आईटीआई, इंटरमीडिएट, स्नातक और एमबीए प्रशिक्षुओं सहित प्रति माह 500 प्रशिक्षुओं को मासिक वजीफा देना शामिल है। नतीजतन, प्रशिक्षुओं ने उद्योग-प्रासंगिक कौशल हासिल किए, जिससे उपयुक्त नौकरी की भूमिकाओं की प्राप्ति या नए व्यावसायिक उद्यमों की स्थापना हुई।

दक्षता: सीएसआर फंड की राशि 300 लाख रुपये थी और बीडीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न अंतरालों पर प्रति माह 500 प्रशिक्षुओं के वजीफे को कवर करने और कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए उपयोग किया गया था।

प्रभावशीलता: बीडीएल ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रति माह 500 आईटीआई/इंटरमीडिएट/स्नातक/एमबीए उम्मीदवार युवाओं को विभिन्न प्रकार के शिक्षु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करके अपने परियोजना उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। इन शिक्षुओं ने मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्रों के साथ उद्योग-विशिष्ट कौशल हासिल किया। इसके अलावा, उन्हें एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि के लिए वृत्तिका प्रदान की गई विभिन्न उद्योगों में प्लेसमेंट या स्वरोजगार के माध्यम से बेहतर आजीविका का अनुभव किया गया।

परिणाम

- सफल शिक्षुओं को व्यापार के लिए उद्योग मान्यता प्राप्त प्रमाणन मिला।
- सफल शिक्षुओं को निजी / सार्वजनिक उद्यमों में समाहित किया गया।
- सफल शिक्षुओं ने स्वरोजगार उद्यम शुरू किया

प्रभाव: इस परियोजना ने प्रति माह 500 आईटीआई / इंटरमीडिएट / स्नातक / एमबीए आकांक्षी युवाओं को प्रासंगिक उद्योग में खुद को स्थापित करने या उपयुक्त क्षेत्रों में उद्यमिता के नए अवसरों में उद्यम करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाकर काफी प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक उम्मीदवार को पाठ्यक्रम के प्रकार के आधार पर 7000 रुपये से 16000 रुपये प्रति माह तक की वृत्तिका मिली, जिससे उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुई। इसके अलावा, इस पहल ने विनिर्माण, निर्माण, बीपीओ और सेवा क्षेत्र के उद्योगों को कुशल जनशक्ति प्रदान की।

सम्बद्धता: यह परियोजना राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना -2 (एनएपीएस -2) के अनुरूप है और इसे देश भर में शिक्षु प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत काम करने वाले शिक्षुओं को आंशिक वृत्तिका देते हुए आर्थिक सहायता प्रदान करना, शिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता बढ़ाना और हितधारकों को वकालत सहायता प्रदान करना शामिल है।

स्थिरता: परियोजना का प्रभाव स्थायी है क्योंकि अधिकांश शिक्षु मूल्यवान उद्योग एक्सपोजर प्राप्त कर रहे हैं, विभिन्न नौकरी की भूमिकाएं मान रहे हैं, और अपने प्रासंगिक कौशल सेट के भीतर नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं। इन सकारात्मक परिणामों ने बीडीएल को भविष्य में शिक्षुओं के लिए अतिरिक्त कौशल विकास कार्यक्रमों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया है।

परियोजना का प्रदर्शन

ओईसीडी डीएसी फ्रेमवर्क वेटेज स्कोर

डीएसी फ्रेमवर्क पैरामीटर्स	प्रदर्शन संकेतक	वेटेज स्कोर
प्रासंगिकता	अति उत्कृष्ट	17
दक्षता	अति उत्कृष्ट	17
प्रभावशीलता	अति उत्कृष्ट	17
प्रभाव	अति उत्कृष्ट	17
स्थिरता	अति उत्कृष्ट	17
कुल स्कोर	अति उत्कृष्ट	85

व्यक्तिगत स्कोर: अति उत्कृष्ट: 17-20; औसत से ऊपर: 13-16; औसत 9-12; औसत से कम: 5 to 8 और बहुत ख़राब: 1 to 4

कुल स्कोर: अति उत्कृष्ट (Scores: 81 to 100); औसत से ऊपर (61 to 80); औसत (41 to 60); औसत से कम (21 to 40) और बहुत ख़राब (1 to 20)

समग्र अवलोकन

- शिक्षुओं को एक वर्ष की इस शिक्षुता अवधि के भीतर सीखने और खुद को विकसित करने के लिए बहुत अधिक प्रेरित किया गया था। इन कौशलों ने उन्हें उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने और नया व्यवसाय शुरू करने के लिए सुनिश्चित किया।
- इन शिक्षुता कार्यक्रमों ने बीडीएल को उच्च उत्पादकता और बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित किया, जिसके परिणामस्वरूप उत्साह से युवा प्रतिभा तालिका में लाई गई।
- परियोजना ने सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में भी सुधार किया क्योंकि उन्हें उचित वेतन पैकेज के साथ शिक्षुता ट्रेइंग कार्यक्रम के पूरा होने के तुरंत बाद रखा गया था।
- परियोजना ने बेरोजगारी को कम करते हुए स्थानीय / क्षेत्रीय नियोक्ताओं को कुशल संसाधनों की आपूर्ति भी की।

About the Centre for Corporate Social Responsibility (CCSR), IPE

The Centre for Corporate Social Responsibility (CCSR) was set up during 2011 to promote training, research, consultancy assignments and document case studies in thrust areas of CSR. The Centre works on the existing body of knowledge, systems, structures, models, and mechanisms associated with different CSR initiatives; it also provides a platform for discussing CSR guidelines and the latest developments in the field. The Institute of Public Enterprise (IPE) has been part of the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India initiative on introducing Corporate Social Responsibility (CSR) as an element of the performance matrix in Central Public Sector Enterprises (CPSEs). IPE was invited to attend the meetings of the Working Group on CSR in 2007-08 and 2009-10 and was nominated by DPE as a Member of the Executive Committee on CSR in 2011 to develop, design and implement courses for CPSEs. Recognizing the importance of the subject and the realization that there is a dearth of experts in this emerging field, it was decided that IPE could play a major role in research, development, and advocacy of CSR. This idea led to the establishment of the Center for Corporate Social Responsibility in 2011 at IPE. The main objectives of the center are:

- To conduct interdisciplinary and collaborative research and document case studies in thrust areas of CSR dealing with contemporary issues and challenges.
- To integrate the existing body of knowledge, systems, structures, models, and mechanisms associated with different CSR initiatives by interfacing with industry and academia.
- To disseminate information about the latest happenings in the CSR field to the people engaged in policy making, policy analysis, policy research, practitioners, and other stakeholders.

PROJECT LEADER

Prof S Sreenivasa Murthy

Director and NLCIL Chair Professor on CSR,
Institute of Public Enterprise
Hyderabad

PROJECT COORDINATOR

Dr J Kiranmai

Head, Center for CSR, and CG,
Institute of Public Enterprise
Hyderabad

TEAM MEMBERS

Mr M Vaman Reddy, Project Associate, IPE

Ms B Deepa, Research Associate, IPE

About Institute of Public Enterprise (IPE)

The Institute of Public Enterprise (IPE) was established in 1964 as an autonomous non-profit society. IPE is a premier AICTE approved management Institute focusing on transforming students into leaders of tomorrow in organizations and society. IPE's key objectives include management education, research, consultancy, and training. In 1995, the Institute launched its first two year full-time Post Graduate Diploma in Management (PGDM) program to provide skilled human resources to meet the requirements of industry.

Keeping in view the market demand, the Institute also launched sector specific PGDM programs in the areas of Marketing, Banking Insurance and Financial Services, International Business and Human Resource Management. IPE's engagement with long-term management education has received wide appreciation from the industry, government, and social sector enterprises. The Institute continuously endeavours to update the content and teaching methodology of its courses based on feedback from the end-users, ensuring the quality, relevance, and utility of all its programs and courses.

IPE is consistently ranked among the leading B-Schools in India in most well-known ranking surveys. IPE has also been awarded a premium accreditation label of the SAARC region, 'The South Asian Quality Assurance System' (SAQS). Over the years IPE has won several awards and honours for its academic & research excellence.

IPE has a very successful track record of running MDPs over a long period of time. IPE also has a strong Research and Consultancy division, which provide consulting services and undertakes research projects for various national organizations. The Institute has been recognized as a 'Center of Excellence' by the Indian Council of Social Science Research (ICSSR), Ministry of Education, and Government of India.

The Governance of the Institute is overseen through a Board of Governors composed of eminent policy makers, academicians, and CEOs of public and private sector enterprises.

INSTITUTE OF PUBLIC ENTERPRISE

Survey No. 1266, Shamirpet V&M, Hyderabad - 500101.
Phone: +91-40-23490900 Fax: +91-040-23490999
www.ipeindia.org